

है वही ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी सीधे-से
नैतिकता करने की नहीं है। भाष विभूतान
में जो व्यर्थ का पैसा इस संस्था पर खर्च हो रहा
है उसके कुछ आंकड़े मेरे पास हैं। आंध्र
प्रदेश में विधान परिषद् के सदस्यों की संख्या
वेयरलैन और डिप्टी वेयरलैन को मिलाकर,
1971-72 में 82 थी जोकि 72-73 में
87 रही। 1972-73 में मात्र तनख्वाह
का खर्च 3,37,800 रु० था। इसके साथ
साथ जो अन्य सुविधायें मिलती हैं जैसे
मैडिकल फैसिलिटीज, किराया बाड़ा इत्यादि
वह अलग है। इसी प्रकार से बिहार विधान
परिषद् में 1975-76 में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष
के वेतन भत्ते का खर्च 36,848 और
1976-77 में 48,000 तथा 1977-78
में 58,000 है। यह मात्र अध्यक्ष और
उपाध्यक्ष का वेतन भत्ता है। इसी प्रकार
सदस्यों के ऊपर 23,62,700 रुपए का
खर्च हुआ। इसी तरह से 1976-77 और
1977-78 में 23,67,200 रुपया का
खर्च है। इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर
में 1973-74 में 3,46,800 रुपए का
खर्च हुआ (अवकाश) इससे मेरा मतलब
यह है कि लाखों रुपया और कुल मिलाकर
करोड़ों रुपया विधान परिषदों में खर्च किया
जा रहा है जिसका कोई औचित्य नहीं है।
ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है कि माननीय
मंत्री जी इस पर पुनः विचार करें और
राष्ट्रीय पैमाने पर मुख्य सचिवों का सम्मेलन
बुलाकर उनको आदेश दें कि अधिलक्ष्य
विधान परिषदों को समाप्त किया जाये।

MR. CHAIRMAN: Are you with-
drawing the Resolution, as requested
by the hon. Minister?

श्री रामजी लाल सुमन : मैं विवदा
नहीं करना चाहता। अगर यह प्रस्ताव
यहां पर पास नहीं होता है तो सारे देश में
इसके लिए एक राष्ट्रीय आन्दोलन चलाने
की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरी बात यह है
कि अगर मैं इसको वापिस लेता हूँ तो, उरुबा
मतलब होगा कि जो कुछ मैंने कहा है उसको
वापिस ले रहा हूँ।

श्री आनित भूषण : रेडोल्फुशन वापिस
लेने का मतलब यह नहीं होता कि जो आदेश
बाधण दिया है वह भी वापिस हो गया।

MR. CHAIRMAN: Now I will put
the Resolution moved by Shri Ramji
Lal Suman to the vote of the House.

The question is:

"This House is of the opinion that
the Upper House (Legislative Coun-
cils) in the States have not served
any useful purpose and in the pro-
cess of legislation they are proving
to be cumbersome and avoidably
expensive and, therefore, the Con-
stitution should be suitably amended
to abolish them as soon as possible."

The motion was negatived.

16.15 hrs.

RESOLUTION RE PUBLIC DISTRI-
BUTION SYSTEM TO CHECK RIS-
ING PRICES

SHRIMATI AHILYA P. RANGNE-
KAR (Bombay North-Central): Sir,
I am moving my Resolution. I beg to
move:

"This House expresses its grave
concern at the steep rise in the
prices of all essential commodities

[Shrimati Abhaya P. Bhargava]

like pulses, edible oils, milk, cloth, footwear, soap, etc. and fall in the prices of all commercial crops like sugarcane, cotton, tobacco etc. and recommends that, with a view to protect the primary producers as well as the consumers, all essential commodities be procured through the State Governments at fair price from the producers and distributed to the consumers through an effective public distribution system supervised by People's Committees to be set up for this purpose."

सभापति महोदय, मुझे दुःख है कि हमारे सिविल सप्लाइज और कामसे के मिनिस्टर, श्री मोहन धारिया जी, इस समय सदन में मौजूद नहीं हैं। हम रोज़ घण्टाघंटों में मंत्रियों और दूसरे लोगों के बयान पढ़ते हैं कि हमारी उन्नत की चीजों के दाम कम हो रहे हैं, लेकिन यह सच्चाई नहीं है, कीमतें हर रोज़ बढ़ती जा रही हैं। फरवरी, 1978 से लेकर मार्च, 1978 तक एक ही महीने में होल-सेल प्राइस इन्डेक्स .68 बढ़ गया है। इन कीमतों के बढ़ने से हमारी सामान्य बरेन्स धोरतों के सामने एक कठिनाई उत्पन्न हो गई है।

आप देखिए—फूड आर्टिकल्स का फरवरी, 1978 में प्राइस इन्डेक्स 169.1 था, लेकिन एक महीने के बाद 169.9 हो गया, .8 बढ़ गया। वे फिर्त होल-सेल प्राइस इन्डेक्स की हैं, रिटेल की नहीं हैं, रिटेल में तो दुगने और तिगुने दाम बढ़ गये हैं। फूड ग्रैन्ड में फरवरी में प्राइस इन्डेक्स 172 था, लेकिन मार्च में 173.1 हो गया। पल्लेज में फरवरी में 243.5 था, जो मार्च में बढ़ कर 247.4 हो गया, इस तरह से एक महीने में पल्लेज के दाम 3.9 बढ़ गये। फ्यूअल, पावर, माइंट और लुब्रिकेंट्स में 3.54 की बढ़ोतरी एक महीने में हुई है। गुगर-आउटसारी के लिए कहा जाता है कि कम कम हुए हैं,

लेकिन उस में भी इस वीरियट में 1.3 की बढ़ोतरी हुई है। इसी वजह से कमीनरी, टूल्स, इन्ड्रियल इन्वैस्टमेंट में भी दाम बढ़े हैं, कॅमिकल्स में भी दाम बढ़े हैं। चावल उन्नत की कोई भी ऐसी चीज नहीं है, जिस में होल-सेल प्राइस इन्डेक्स कम हुआ है।

छोटी-छोटी चीजें, जिनकी बोरलों को रोष उन्नत पड़ती है, जैसे धनिया, उस के दाम 40 से 50 पैसे किलो बढ़े हैं, सास बिर्न का दाम साढ़े पांच रुपये किलो था, लेकिन उस का दाम अब तवा-छ रुपये किलो हो गया है। आप के बजट के पीके पर गुगर की एक्स इज इयूटी कम की थी, उसके बावजूद भी उस समय गुगर के दाम बढ़े थे। इस साल हर चीज का उत्पादन बढ़ा है। लोग कहते हैं कि उत्पादन कम हो और डिमांड ज्यादा हो तो दाम बढ़ जाते हैं, लेकिन इस साल तो हर चीज का मैक्सिमम प्रोडक्शन हुआ है, फिर भी कीमतें बढ़ रही हैं; इस का क्या कारण है? इस का एक ही कारण है कि ट्रेडज जान-बूझ कर कीमतें बढ़ा रहे हैं, वे माल को अपने गोदामों में होर्ड कर रहे हैं और हमारी सरकार को इस की कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि वह आपस के झगड़ों में लगी हुई है। लोगों की तकलीफों के बारे में सरकार का कोई ध्यान नहीं है, वह इस में कोई दखल नहीं दे रही है।

एक और बात आप को बतलाती हूँ—चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं, जब कि प्रोडक्शन हर चीज का बढ़ रहा है। कास्ट का प्रोडक्शन बढ़ गया, गुगर-केन का प्रोडक्शन बढ़ गया, लेकिन कपड़े के दाम बढ़ने और गुगर के दाम बढ़ने का लाभ उस के उत्पादक को नहीं मिला। जो कास्ट का उत्पादन करता है, जो गुगर-केन का उत्पादन करता है, उसकी कीमतें उल्टा कम हो गई, उसको कम दाम मिले, लेकिन मिल जायिकों

को, उसे लेकर आती है, जो कपड़ा बनाते हैं, इन को उस का भाग मिला। हमारी सरकार का एक नया तरीका यह रहा है— जिस चीज की कीमत बढ़ जाती है, वह उस चीज का इम्पोर्ट करना शुरू कर देती है, वह देखने का प्रयास नहीं करती है कि उस वस्तु की कीमत क्यों बढ़ी है। जैसे 'मिड' की कीमत बढ़ गई है, तो उसका इम्पोर्ट शुरू कर दिया है। मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ—सोडा-ऐस का। सबा-प्रति बहुदय, सोडा ऐस कांच के उत्पादन में सक्षम है और सोडा ऐस का प्रोडक्शन भी कमी बढ़ गया है और यह 1800 रु० प्रति टन हो गया है जो कि पूरे देश की जो सोडा ऐस की जरूरत है उस से ज्यादा है लेकिन फिर भी इस को बाहर से मंगाने की बात की जाती है। सोडा ऐस का उत्पादन किस के हाथ में है? 56 परसेंट टाटा, 33 परसेंट बिरला, 7 परसेंट जैन के हाथ में और साहू के हाथ में 4 परसेंट है। इस तरह से बड़े लोगों के हाथों में इस का उत्पादन है और हमारे देश की जनता को जितनी इस की आवश्यकता है, उस से ज्यादा उत्पादन है लेकिन कीमतें इन्होंने बढ़ा दी हैं। पहले 1200 रुपये टन इस की कीमत थी, जिस को बढ़ा कर इन्होंने 1900 रुपये टन कर दिया है और हमारी जो यह गवर्नमेंट है, इस ने इस बारे में क्या किया? जब इन लोगों ने पूछा गया कि इस की कीमत इतनी क्यों बढ़ गई है, 1200 रुपये प्रति टन से बढ़ कर 1900 रुपये प्रति टन क्यों इस की कीमत हो गई है, जो बहुगुणा जी कहते हैं कि हम सोडा ऐस इम्पोर्ट करेंगे। हर चीज इम्पोर्ट करने की बात करते हैं और यह नहीं देखते हैं कि कीमतें क्यों बढ़ गई हैं। वे जो बड़े बड़ पूंजीपति हैं, इन के पुमाऊ बहुत बढ़ गये हैं। इमर्जेंसी के दिनों में इन के प्रीफिट इतने बढ़ गये हैं कि एक कम्पनी जिस को प्रीफिट 20 करोड़ रुपये था, वह बढ़ कर 222 करोड़ रुपये हो गया। यह

इसलिए होता है कि इन की वजह से हमारे देश में और एक प्रश्न है कि इस को रोकने के लिए क्या रास्ता निकाला है, तो कहते हैं कि हम इम्पोर्ट करेंगे, सोडा ऐस इम्पोर्ट करेंगे। आज जो सिलिकोन के कारखाने हैं, कांच के कारखाने हैं, वे बन्द हो गये हैं और हमारे मछुइरों को काम नहीं मिल रहा है लेकिन गवर्नमेंट का ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा है।

इसी तरह से तेल की बात है। तेल के बारे में कहते हैं कि हम इम्पोर्ट करेंगे और इम्पोर्ट करने के बाद नया होता है। अभी इकोनामिक्स टाइम्स में एक लेख निकला था, जिस में बताया गया था कि जो तेल इम्पोर्ट किया गया था, वह बम्बई में पड़ा रहा। वह खाने लायक नहीं है। हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि हम इस को दूसरे देशों में भेजेंगे और इस से हमें फारेन एक्स-चेन्ज मिलेगी। फारेन एक्सचेंज कमाने के लिए जो चीज बाहर से आती है, उस को भी बाहर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। इस तरह का धाप का इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का तरीका चल रहा है। इसलिए कोई सही रास्ता इस के हल के लिए नहीं निकाला जा रहा है।

वेजीटेबल्स की प्राइसेज धाप देखिए कि कितनी बढ़ गई हैं। मेरे पास बहुत सी फीगर्स हैं लेकिन मैं टाइम ज्यादा न होने के कारण सिर्फ प्याज का ही उदाहरण देती हूँ। जो प्याज पहले 75 पैसे किलो बिक रही थी, वह अब 1 रु० 40 पैसे और 1 रु० 50 पैसे किलो बिक रही है। जो प्याज पैदा करता है, उस किसान को प्याज का कितना मूल्य दिया जाता है? उस किसान से प्याज 25 पैसे किलो के हिसाब से आती है और बाजार में आ कर 1 रु० 40 पैसे और 1 रु० 50 पैसे बिकती है। बीच में इतना पैसा कौन ले जाता है? टमाटर की भी

[श्रीमती अहिष्का पी० खन्नेकर]

यही हालत है। यह सब ऐसा बीच के जो ट्रेडर्स हैं, वे ले जाते हैं। जब हम ने गवर्नमेंट से धीरे भीहन धारिया से इसके बारे में कहा, तो उन्होंने कहा कि हम स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन और नेकेड द्वारा उनसे आइरेक्टली लेगे धीरे इस तरह से बीच का मुनाफा कम हो जाएगा। हम ने पूछा था कि इस में खर्चा कितना आता है? अगर एक किलो पर 15 पैसे खर्च आते हैं, तो किसान को अगर 50 पैसे दे दें, तो बाजार में आकर वह 60, 65 पैसे किलो कन्ज्यूमर्स को मिल सकता है, लेकिन जब नेकेड के अधिकारी वहां गये तो क्या हुआ कि ट्रेडर्स ने पहले से ही झण्डा माल अपने पास रख लिया और गन्दा माल नेकेड को दे दिया और ट्रेडर्स के बारे में धाय उंगली नहीं उठाते हैं। ट्रेडर्स खुश हैं क्योंकि उन को मालूम है कि अगर वे प्राइसेज को रोक करते हैं तो गवर्नमेंट उन का कुछ करने वाली नहीं है। उन्हे उन को इम्पोर्ट करने के लिए धीरे कन्सेशन सरकार दे रही है और इन कन्सेशन का वे फायदा उठा रहे हैं। एक तरफ वे प्राइस बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ उन को इम्पोर्ट लाइसेंस और दूसरे कन्सेशन सरकार दे रही है लेकिन इतने पर भी प्राइस कम नहीं हो रही है। गवर्नमेंट इस के बारे में कुछ नहीं कर रही है।

होडिंग के बारे में धाय देखते हैं कि क्या हालत है। मैं धाय को दालों की मिसाल देती हूँ। बम्बई में महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने ऐसा किया कि एक हजार बोरी वहां दालों की है और इस से ज्यादा नहीं है। धाय को मालूम होगा कि हम 100 धोरतों को से कर हर एक गोदाम में गये धीरे छापा मारा। हमसे कहा गया था कि एक हजार बोरियां हैं, लेकिन हमें कहा था कि 34 हजार बोरियां मिलीं। यह धाय के व्यापारियों की हालत है। धायको

इन दाल के व्यापारियों की जांच करनी चाहिए। मैं पूछना चाहती हूँ कि इन दाल के व्यापारियों से सम्बन्धित इस हाउस में कौन है। उनसे सम्बन्धित कौन इस हाउस में आकर है इसलिए दाल के व्यापारियों को संरक्षण मिल रहा है और वे भाव बढ़ाने की हिम्मत करते हैं। कहा जाता है कि दाल का उत्पादन कम है। मैं कहती हूँ कि दाल का उत्पादन इतना कम नहीं है जितना कि इसके भाव बढ़े हैं। जब दाल का उत्पादन कम है तब भी किसान को प्रोटेक्शन नहीं मिलता है जब किसान उत्पादन बढ़ाता है तब भी धाय उसको प्रोटेक्शन नहीं देते हैं। ये ट्रेडर लोग कमाते चले जा रहे हैं। इस सब की धायको जांच करनी चाहिए। दाल की कीमतें कम लाने के लिए धायको होडिंग बन्द करनी चाहिए।

हमारी गवर्नमेंट कहती है कि इन्फ्लेशन कम हो रहा है। यह केवल दो परसेंट है। लेकिन हम देखते हैं कि यह कम नहीं हो रहा है क्योंकि इसके ऊपर भी धायका कंट्रोल नहीं है। देश में काला पैसा बहुत है। आपने एक हजार रुपये के नोट बंद किये, इसका बोझ सा घर पर हुआ होगा लेकिन काला पैसा कम नहीं हुआ। धाय सोने की नीलामी कर रहे हैं। नीलामी में सोना कौन खरीद रहा है? बड़े बड़े व्यापारी खरीद रहे हैं। धारविन्दी सुनार को सोना नहीं मिलता है। जब वह सोना भी बड़े-बड़े व्यापारी, बम्बई में रहने वाले बड़े बड़े ट्रेडर यह सोना ले जावेंगे और छोटे सुनार को यह नहीं मिलेगा तो इन्फ्लेशन कैसे कम होगा? हम देखते हैं कि बम्बई में सम्बन्धित धायों की ही रही है। बम्बई में रात को क्वीटेन्स की स्मलिंग होती है। स्मलिंग पर भी धायका कोई कंट्रोल नहीं है। इसी की वजह से क्वीटेन्स के धाम बढ़ते हैं। हमने अभी देखा, दिल्ली में आपने उबल दोग दूध

के बावजूद 15 नई बड़ा थिये । आगकी बड़ा नहीं है कि आपके दूध के पाउडर की भी संश्लेषण होती है और वह दूध की कण्ट्री की बना रहा है । इस सब के बारे में बचनमेंट को कुछ करना चाहिए ।

हमने देखा कि हमारी बचनमेंट ने सीमेंट की प्राइस भी बढ़ा दी । आपके बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स सीमेंट का पूरा उत्पादन नहीं करते हैं । हमारी जितनी सीमेंट की प्रोडक्शन केपेसिटी है, वह पूरी क्षमता में नहीं घाती है । आप देखेंगे कि हमारी प्रोडक्शन केपेसिटी का 20, 25 या 50 परसेंट तक ही उत्पादन होता है । अगर हम अपनी पूरी प्रोडक्शन केपेसिटीकाम में लायेंगे तो हमारा सीमेंट का प्रोडक्शन बढ़ेगा और इससे लोगों को सीमेंट की शार्टेज महसूस नहीं होगी ।

रिजर्व बैंक की रिपोर्ट मैंने देखी है । रिपोर्ट में कहा जाता है कि सबूत हड़ताल करते हैं इसलिए उत्पादन कम होता है । लेकिन आज भी जो लोक आऊट चल रहे हैं उनके बारे में कुछ नहीं कहा जाता । इस सम्बन्ध में मैं इतना प्रबन्ध कहूँगी कि इस लोक आऊट में जो लोग शामिल हैं वे कापेस के एम० पी० हैं । उन्होंने इसका प्रोधात चालू किया है । लोक आऊट को इस्लीमल करार दिया हुआ है फिर भी यह चल रहा है । यह सब क्यों हो रहा है ?

आपने कोयले पर एक्साइज इवटी बढ़ाई, उससे कोयले की कीमत बढ़ गई । मुगारकेन पर आपने एक्साइज इवटी कम कर दी, उससे मुगारकेन की कीमत तो कम हो गई लेकिन चीनी के दाम बढ़ गये । ये ट्रेडर्स लोग होडिंग करते हैं फिखसे ये प्राइसिज और बढ़ जाती हैं । पहले चावल इस्ता मिलता था लेकिन अब कोई भी चावल

दिल्ली में आकरने किसी से कम नहीं मिलता है । आगे इसकी कीमतों पर टोक नहीं लगाई तो आप एक साल के बाद देखेंगे कि चावल पूरा का पूरा होडिंग में चला जाएगा और गरीब लोगों को कुछ नहीं मिलेगा । इसी तरह से सोप के बारे में । ये मल्टी मिसियनर्स बेन्चर आफ कापर्स में मोहन धारिया जी को और मोरारजी भाई को हार पहुनाते हैं और कहते हैं उन्होंने घोषणा की थी कि हम प्राइस फ्रीज करेंगे । उन्होंने कहा था कि 31 दिसम्बर तक प्राइस फ्रीज करके रखेंगे । क्या उन्होंने ऐसा किया है ? टाटा, जिडला वगैरह तक ने कीमत बढ़ा दी हैं । तीन महीने में ही बढ़ा दी हैं । एक तरफ भालाएं पहनाई जाती हैं और घोषणा की जाती है कि हम प्राइस फ्रीज करके रखेंगे और दूसरी तरफ 31 दिसम्बर, से पहले पहले 25-30

परसेंट प्राइसिज को बढ़ा दिया जाता है । बाकी की जो चीजें हैं वहाँ पर उन में तो 50-55 परसेंट बढ़ा दी गई हैं । क्या यह प्राइस फ्रीज हुआ है । एक और चालाकी उन्होंने चली है । साबुन में उन लोगों ने फ्रंट कंटेंट को कम कर दिया है । साइज वही है, प्राइस अगर कम भी करदी है तो चालाकी यह की है कि फ्रंट कंटेंट कम कर दिया है । माननीय ज्योतिर्बस बसु ने सवाल उठाया था तेल का । पोस्टमैन तेल बहुत चलता है बहुत महंगर है । अगर इस में मिलावट होती है तो किस को पकड़ा जाता है ? मीनेजर की पकड़ा जाता है । क्यों नहीं मैं पूछना चाहती हूँ कि बेयरमैन और ट्रस्टी को आप पकड़ते हैं । दूसरी जगह पर मिलावट होती है और कोई केस पकड़ा जाता है तो उस में आप आफिस में काम करने वाला जो चपड़ासी है उसको पकड़ते हैं । मैं पूछना चाहती हूँ कि क्यों नहीं आप बेयरमैन और मीनेजर को पकड़ते हैं ? उनको आप छोड़ देते हैं और चपड़ासी को पकड़ लेते हैं मिलावट करने के

[श्रीमती महिल्या श्री. राजेकर] कुर्मी में। बेबरमैन को यहाँ नहीं पकड़ते हैं। इन बड़े लोगों के खिलाफ आप कदम नहीं उठाते हैं। पुरानी सरकार का जो तरीका था वही तरीका आप ने भी प्रचलित कर रखा है। उसी तरीके से आपका काम भी चालू है। आप सीरियस नहीं हैं इन सब बातों के बारे में।

श्री मोहन धारिया ने कहा था जहाँ 20 हजार से ज्यादा लोगों की बस्ती है वहाँ हम डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर खोलेंगे। उन्होंने कहा था कि देश में 2 लाख 20 हजार इस तरह के सेंटर खोलने वाले हैं, छोटी छोटी सरकारी दुकानें खोलने वाली हैं। वहाँ पर लोगों को जबरत को दस चीजें मिलेंगी। आपने चावल को छोड़ दिया था। आपने कहा था कि वहाँ पर तेल, मसाले, कपड़ा, मैरोसीन आपन, माचिस, सोप आदि इस तरह से दस चीजें मिलेंगी। उनकी घोषणा थी कि हम 2 लाख 20 हजार इस तरह के सेंटर खोलने वाले हैं उन जगहों पर जहाँ पर बीस हजार से अधिक की बस्ती है। इस घोषणा को किए हुए छः महीने से ज्यादा का समय हो गया है। मैं पूछना चाहती हूँ कि कितनी इस तरह की दुकानें आपने खोली हैं। अभी तक एक भी नहीं खोली है। आपके द्वारा एलान करने के बाद, आश्वासन देने के बाद छः महीने में एक सेंटर भी आपने नहीं खोला है तो आपने आप पर किस तरह से विश्वास किया जा सकता है।

मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि जो प्रोड्यूसर है उसको उसकी प्रोड्यूस की आपको उचित कीमत भी देनी चाहिए। एस टी सी की स्थापना आपने कर रखी है। लेकिन वहाँ भी आपको आमूम ही है कि

प्रोड्यूसर जाता है। फार्मिन्ग प्रोड्यूसरों की प्रोड्यूसर से लिया है। उनको प्यास की खरीद की थी। जिन लोगों ने कुछ दे दिया उनकी प्यास तो खरीद कर ली गई थीर बाकी लोगों को खरीद नहीं की गई। उनका एक डेपुटेमन भी यहाँ थावा था थीर भी मोहन धारिया से किया था। मैं कहना चाहती हूँ कि वहाँ जो प्रोड्यूसर है वह भी समाप्त होना चाहिए। जोड़मारी जबरत की चीजें हैं उनको एस टी सी नहीं तो नाफिड को सोवे प्रोड्यूसर से खरीदना चाहिए। शर्त यह है कि जो प्रोड्यूसर है उसको ठीक कीमत मिले।

आप गरीब आदमी का खास खयाल रखें। आप एक इनकम फिक्स कर दें। पांच सौ छः सौ या सान सौ से कम जिस किसी का आयदनी हो उसको आप सबसिडिइज तरह के जबरत की चीजें दें। जो दरिद्रता को रखा से नीचे रह रहे हैं उन लोगों को सबसिडिइज कर के आप इन बन्धुओं को दें। आप इन्फोर्ट के लिए कंसेशन देते हैं। आप जो प्रोड्यूस करता है उसको कंसेशन दें। इन दरिद्रता को रखा से नीचे रहने वालों को आप सबसिडिइज करके उनको जबरत की चीजें दें। आप इसके लिए कोई इनकम की सीमा धाब सकते हैं, उनके लिए अगर आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से इस तरह का प्रकथ कर देंगे तो जनता को थीर गरीब लोगों को कुछ राहत मिल सकेगी। नहीं तो चाब जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं उस तरह से बढ़ते चले जाएँगे। आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते।

रेडियो से आप बोधगार्व करते हैं कि हीलसेल प्राइसिड इतनी कम हो गई है या इतनी बढ़ गई है। लेकिन आप देखें

कि अगर होलसेल प्राइस 1 परसेंट बढ़ती है तो रिटेल प्राइसिस 25-30 परसेंट बढ़ जाती हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप इस तरह की घोषणायें रेडियो से करना बन्द कर दें। जो भाव रेडियो पर दिये जाते हैं, बाजार में हमें कभी भी वे भाव नहीं दीखते हैं। कभी-कभी हम देखते हैं कि कई चीजों के लिए हमें सुपर बाजार में बाहर से ज्यादा कीमत देनी पड़ती है।

मैंने सुना है कि किसी ने यह ऐलान किया है कि राशनिंग बन्द होने वाला है। कृपा करके राशनिंग को बन्द न करें। हमें मालूम है कि आज राशनिंग में जो माल मिलता है उसको जानवरों के सिवा कोई नहीं खायेगा। बम्बई में जो चावल बारिश से बुराव हो गया वही राशनिंग में दिया गया। उसकी क्वालिटी को सुधारना चाहिए।

पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रल के द्वारा केवल अनाज ही नहीं बल्कि कचड़ा, साबुन, तेल, मसाला और केरोसीन आयल आदि अन्य जरूरत की चीजें भी दी जानी चाहिए। इसके अलावा घर बनाने के लिए सीमेंट भी कंट्रोल रेट पर दिया जाना चाहिए। बम्बई में मजदूरों के लिए मकान बन रहे हैं और 160 स्क्वेयर फीट के लिए 160 रुपये भाड़ा तय किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इसके लिए सब्सिडी नहीं देंगे। स्टील और सीमेंट के दाम बढ़ने से भी महंगाई में वृद्धि होती है। अगर सरकार सीमेंट को कंट्रोल रेट पर देने की व्यवस्था करे तो इससे भी लोगों को बहुत राहत मिलेगी। सरकार कहती है कि हम सबको गैस देने वाले हैं। वह उचित दाम पर दियासलाई तो दे नहीं पाई है गैस तो बहुत दूर की बात है।

जहां तक विजिलेंस कमेटी का प्रश्न है दिल्ली में भी महिलाओं की दक्षता समिति ने

बहुत अच्छा काम किया है जिसकी सेक्रेटरी श्रीमती प्रमिला दण्डवते हैं। उसने अफसरों को बताया कि अमुक अमुक जगह पर होर्डिंग की गई है आप उसको देखें। बम्बई में महंगाई प्रतिकार समिति ने भी यही काम किया है। यह आवश्यक है कि दक्षता समिति को इन्स्पेक्शन का अधिकार दिया जाए। अगर हम कहीं देखने के लिए जाते हैं तो वे लोग कहते हैं कि आप कौन हैं। बम्बई में ऐसा अधिकार दिया गया था जिसके कारण होर्ड किया हुआ तेल बाहर आ गया। विजिलेंस कमेटी को इन्स्पेक्शन का अधिकार देने के अलावा अगर उनको लगता है कि कहीं पर होर्डिंग की जा रही है तो उनको पुलिस में शिकायत करने का अधिकार भी देना चाहिए। दक्षता समितियों को ये अधिकार देने से होर्डिंग और महंगाई की समस्या को हल करने में मदद मिल सकती है।

आखिर में मैं कहना चाहती हूँ कि लोग तंग आ गए हैं। औरतों तो बहुत तंग आ गई हैं। औरतों में पृच्छती है कि हमारा बेलन कहाँ है।

श्री कंबर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : किसको बेलन मारना है ?

श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर : हमको मालूम है कि किसको मारना है। होर्डिज को बराबर यह बताया गया है।

श्री कंबर लाल गुप्त : उसको घर में इस्तेमाल न किया जाए।

श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर : आपकी बीबी आपको कभी बेलन नहीं मारेगी।

मैं इशारे से कहना चाहती हूँ कि अगर स्थिति में सुधार न हुआ तो हिन्दुस्तान की औरतों को एक दफा फिर बेलन उठाना पड़ेगा।

MR. CHAIRMAN: Resolution moved.

"This House expresses its grave concern at the steep rise in the prices of all essential commodities like pulses, edible oils, milk, cloth, footwear, soap, etc. and fall in the prices of all commercial crops like sugarcane, cotton, tobacco, etc. and recommends that, with a view to protect the primary producers as well as the consumers, all essential commodities be procured through the State Governments at fair price from the producers and distributed to the consumers through an effective public distribution system supervised by People's Committees to be set up for this purpose."

MR. CHAIRMAN: Now Mr. Yuvraj is to move an amendment. He can speak later.

SHRI YUVRAJ (Kathihar): I beg to move:

That in the resolution,—

(i) after "soap" insert "cement"

(ii) after "tobacco" insert "jute"

(iii) add at the end—

"and action be taken against malpractices and corruption in the distribution system on the basis of the reports received in this regard." (1).

MR. CHAIRMAN: Mr. Anant Dave is not present.

SHRI RAM VILAS PASWAN (Hajipur): I beg to move:

That in the resolution,—

add at the end—

"and parity be maintained in the prices of industrial products and agricultural commodities." (2).

SHRI V. M. SUDHEERAN (Alleppey): I rise to support the resolution moved by Shrimati Ahilya Rangnekar.

A very serious situation has developed because of the alarming rise in prices. As the mover of the resolution has already stated, the prices of all the essential commodities have risen. The common people, the middle class people, those who belong to the fixed income groups are the worst sufferers. The official wholesale price has taken a sharp upward turn during the last one month, upsetting all the calculations of the Finance Minister. The increase has been as much as 3.3 per cent in the month of June alone, of which 0.6 per cent was in the last week itself. This is equal to the worst days of price rise four years back.

The present Government has totally failed to check the price rise in all essential commodities. Although the Ministers concerned speak well, very cleverly, very beautifully prices have kept up their rise. Some of the essential commodities are not even available these days. The prices of pulses, edible oils, rice, wheat, fresh vegetables, kerosene, cement and all the essential articles have risen, and some of them are not even available in the market.

It is widely reported that hoarding and blackmarketing are taking place throughout the country. The hoarders and blackmarketeers are misusing the freedom prevailing in the country. Our Prime Minister had stated earlier that now there is freedom from fear, but it is very clearly indicated that now the hoarders, blackmarketeers and the anti-social elements are free from fear. They are taking advantage of the situation prevailing in the country. No adequate checks are there to prevent them from indulging in anti-social activities.

While the prices of industrial commodities are very high, agriculturists and cultivators are not getting a remunerative price for their produce. The paddy cultivators throughout the country are not getting remunerative

prices but the price of rice has gone up. The wheat cultivators are not getting a reasonable price for their produce, but the price of wheat has gone up. The tobacco growers are not getting reasonable prices for their produce, but the price of cigarettes and other items has gone up. The sugarcane growers are the worst sufferers. They are not getting reasonable prices for their produce, but the price of sugar has gone up, and it is not also available.

In Kerala we produce paddy, but our paddy producers and cultivators are not getting sufficient price, and they are put to trouble. I would like to point out the problem of the paddy cultivators of Kuttanad, the water-logged area of Kerala. The total area of Kuttanad is 1,25,000 acres with an annual yield of 3,000 tonnes of paddy. The 25,000 cultivators of Kuttanad are forced to boycott cultivation this year because their just and reasonable demands have not been properly met. They are not getting remunerative prices for their produce, while the cost of production is very high. De-watering of the fields is the first among the various agricultural operations in the paddy belt. The fixation of the year's pumping subsidy is stated to be the most important issue concerning the cultivation of paddy. The paddy cultivators of Kerala also demanded a floor price for paddy and stoppage of all recovery measures in respect of the dues to the Government. The problem of cultivation in 5,000 acres of Kariland cultivation in my constituency near Alleppey, and the problem of the cultivation of the Kole land in Trichur have to be attended to.

The Kerala Government is very keen to solve all the problems, but the present financial position of the State Government is not sound enough to meet the just demands of the paddy cultivators of Kuttanad. Anyway, the Kerala Government has declared a support price for paddy.

That is a welcome move. So, I would appeal to the Union Government to provide sufficient funds to the Government of Kerala to enable them to meet the just demands of the paddy cultivators of Kuttanad.

The Government of Kerala has declared a support price for tapioca also. That is a very welcome move. But the point is that the cost of production has increased much while they are denied reasonable prices. That is the phenomenon throughout the country. Whereas industrial manufacturers and traders are getting high profits, the poor peasants, the paddy cultivators, the wheat cultivators, the tobacco cultivators, the sugarcane cultivators are not getting sufficient or reasonable prices.

It is the evil influence of the monopoly houses on this Government, it is the evil influence of the traders and big businessmen on this Government that has led to the worst situation which is prevailing in the country. I am very sorry to say this, that the present Government is patronising the blackmarketeers, the hoarders, the monopolists that is why this situation has been created. So, I request the hon. Minister, through you, to take appropriate steps to check blackmarketing, hoarding and all this type of anti-social evils, and introduce an effective public distribution system.

Our Ministers have talked about introducing an efficient and effective public distribution system, but it has not been introduced so far. It is only a statement in the papers. What is this, Sir. Is it fair on the part of the Government to say something only in the papers and not implement it to meet the needs of the people? The people of this country are keenly watching what this Government is doing. If they are honest and sincere enough, they should take effective steps against hoarders, black-market-

[Shri V. M. Sathyanarayanan] :
ers and other anti-social elements
and introduce an effective distribution
system. The people of this country,
the common people, the labourers, the
middle-class people are the worst
sufferers because of the price rise. It
is high time that this Government
should take steps in this direction.

With these words, I support the
Resolution moved by Smt. Ahilya
Rangnekar.

MR. CHAIRMAN: There is a large
number of hon. Members who want
to speak on this Resolution. I there-
fore, request them not to take more
than 7 minutes.

SHRI DINEN BHATTACHARYA
(Serampore): I request you to kindly
suspend the Rules so that I may be
able to move my Resolution.

MR. CHAIRMAN: You move it at
5.30.

SHRI BALWANT SINGH RAMOO-
WALLA (Faridkot): The Resolution
which has been moved by an hon.
Member of the House, needs sincere
attention. It should be taken very
seriously. The situation on the price
front in this country is getting wor-
sened day by day. The Hoarders and
black-marketeers are having their
heyday. I will humbly request that
nothing will be gained by putting
blame on this side or that side. If
this House and the Members of this
House are really loyal to their voters,
loyal to the people in this country,
to the poor people, किसान, low-income
groups, fixed income groups, to the
people who were hard, to those chil-
dren who are working, we should
take a bold stand unflinchingly against
these hoarders and black-marketeers
as we take a united stand against the
foreign invaders, who invade our ter-
ritory.

Our Congress brothers have
brought the heyday to these hoarders.
They have taught them how to pass-

tra into the Government. Govern-
ments may change in the State, Gov-
ernments may change at the Centre,
but these people have trained them
how to penetrate into the Govern-
ment and how to get the things done.
The Members of this august House
should unite against the hoarders.
Cement is being sold in black. See
the position in Punjab. If railway
trains have been cancelled. Yesterday,
I raised this question in the House.
Then many Members said that trains
had been cancelled in their States
also. On the one hand, the Railway
Minister says, "We are surplus in wa-
gons" and, on the other hand, the
Energy Minister says, "we are sur-
plus in coal" but the reason given by
the Government for cancelling the
trains is "We are cancelling the
trains because the coal is not there,
the coal is in shortage". One is asto-
nished at that. The Energy Minister
in this House says, the coal is in
abundance; the Railway Minister in
the Rajya Sabha says, the wagons are
in abundance. But the trains are being
cancelled because the coal is not be-
ing supplied. This is the position
of the Government. The Government
must take the responsibility in this
matter.

I would like to bring to the notice
of this august House that in Punjab
one good thing has been done. In
Punjab, the State Government has
opened 3000 cheap rate shops by the
Food Corporation of the State. In
these shops, for all the 12 months of
the year, the Punjab Government has
given the guarantee that moong will
be sold at Rs. 3.00 per kg.; mash—
Rs. 3.40 per kg.; washed moong—Rs.
4.00 per kg., washed mash—Rs. 4.00 per
kg., mustard oil—Rs. 6 per kg., wheat
and atta—Rs. 1.20 per kg. and ghee
—Rs. 7.30 per kg. These are the es-
sential items which are needed by the
poor man. The Punjab Government
has done it. Why not the Central Gov-
ernment also do it, if not in the States,
at least in the union territories. The

Central Government should give the guidelines:

I would say that the trader of this country, the manufacturer of this country, the big industrialist of this country, is a blood sucker. They are sucking the blood of the poor, the worker, the peasant, the common man in the street. I would like to bring to the attention of the House as to how clever they are. Take, for example, the match industry. They say that they have reduced the price of a match box. They reduced the price of a match box by 2 p. but reduced the number of match sticks from 60 to 40 in the match box. Very cleverly, they say that they have reduced the price by 2 p. but the actual loss to the consumer is 6 p. The trader, the manufacturer, the industrialist, is a very clever person, a cheat, a professional person, who knows how to cheat, how to deprive the consumer of his money.

All emphasis is being given on packaging. The things inside are of very inferior quality. Inferior quality things are packed in very good packages. They are sold at high prices. The Government should issue strict orders saying that the packaging should be very simple. At least the advertisement cost should not be included in the manufacturing cost.

Lastly, in my constituency, the American cotton growers are being fleeced. In Faridkot, Jaitu, Malot, Bhatinda, Mukatsar, Rampuraphul, Rama, etc. in those areas of Punjab the American cotton is produced. In 1977, the price of American cotton in these mandis was Rs. 500. This year, it was Rs. 250.

17 hrs.

The textile owners are destroying the economic of the poor peasants. The poor peasants are at the mercy

of these textile owners. I will humbly request the Government to give Rs. 200 crores interest free to the Punjab Government to enable them to start their own cotton corporation so that Punjab Cotton Corporation may come to the rescue of these poor peasants.

In the end, I will humbly request this House—I hope everybody will support me very seriously—that this House should tell the Government to appoint a commission consisting of Members of Parliament—not Shah Commission or any other commission—and that commission should go into details. They should compare the increase in prices between the agricultural commodities and the industrial output. In my opinion, in the last eight years, the prices of agricultural commodities have risen 20 per cent whereas the prices of industrial products like tractors, tube-wells, machinery, pesticides and fertilisers, have risen by 300 per cent. With these few words, I conclude my speech. I am thankful to you.

श्री कंबरनाल गुप्त (दिल्ली सदर) :
अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव सदन के समय है उसका सिद्धान्त रूप में मैं समर्थन करता हूँ, क्योंकि यह तो हरेक व्यक्ति स्वीकार करेगा कि चीजों के भाव नहीं बढ़ने चाहिये। चीजें सधी को ठीक दाम पर मिलनी चाहियें, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। पर अपनी कांग्रेस के मेरे भाई जनता पार्टी को कह रहे थे और महिल्या जी भी जनता पार्टी को कह रही थी कि हम फ़ैक्ट्रीज्बानल कम्पनीज के स्वयं हैं, होर्स के साथ मिले हुए हैं और लोक प्रतिक्रियर्स के साथ मिले हुए हैं। उन्होंने कहा कि देश में सहगई बहुत ज्यादा है। मैं उनको बताता चाहता हूँ कि वस्तु-स्वयं लि क्या है ?

देश में प्रवेश, मैं और जून 1976 में प्रारंभ में 3.2 परसेंट की इंडीक्स हुई

[श्री अंबर लाल गुप्ता]

की। इस तीन महीनों में, 1977 में यह इन्फ्लेक्शन 2.3 परसेंट की हुई। 1978 के इन तीन महीनों में यह इन्फ्लेक्शन 1.6 परसेंट की है। इसका मतलब यह है कि 78 में सब जो वाम बढ़े हैं वे करीब करीब आगे बढ़े हैं। यह कहने का मेरा मतलब यह नहीं है कि वाम बढ़ने चाहिए। लेकिन मेरा कहना यह जरूर है कि कीमतों के मामले में, देश में पहले से हालत बराबर है, यह कहना तथ्य से परे है, ठीक नहीं है। यह बात बड़ी लोग कह सकते हैं जो सच्चाई को नहीं जानते या तथ्यों की जिन्हें जानकारी नहीं है।

हाल में मुझे बिदेस जाने का मौका मिला। इस साल तीन महीनों में हमारे यहाँ 1.6 परसेंट प्राइस इन्फ्लेक्शन हुई। अब जरा देखिए कि इन्फ्लेक्शन में कितनी हुई एजिया में कितनी हुई और अमेरिका में कितनी हुई?

I went to Russia. There is an open market in Moscow; otherwise it is all controlled by the Government. There is only one open market, the vegetable market, in Moscow. I returned only three weeks back: there the prices of tomato was Rs. 25 a kilo and similar is the case with onions. Even for ordinary vegetables, I was told, prices have gone up by three to four times in Moscow. If I am wrong, I am prepared to take the responsibility and give a public apology. But the fact remains. You may go to England, America or any other country; the speed of rise in prices is much more than in India.

कहने का मतलब यह नहीं है कि जो कुछ हो रहा है वह बिल्कुल तत्कालीनक हो रहा है और उसमें सुधार की गुंजाइश नहीं है। सुधार की गुंजाइश है और बहुत है। बीजाप्य से हमारे पास दो बार्से बहुत अच्छी हैं। हमारे पास बकर स्टॉक काफी है। हमें इस बात की चिन्ता नहीं है कि अगर अनाज की कमी पड़ेगी तो कहाँ से आएगा। हमारे पास 17-18 मिलियन टन अनाज है। साब ही साब हमारे

पास एक दूसरा हथियार भी है। हमारे पास कारेन एक्सचेंज काफी है। अगर किसी चीज का अभाव होता है तो उस चीज को हम बिदेसों से मंगा सकते हैं और देश में अन्न चीज को सुरक्षित कर उसके बाव-झीक कर सकते हैं। इन चीजों हथियारों के होते हुए भी मैं समझता हूँ कि सरकार को और ज्यादा एक्टिविटी विचारनी चाहिए। इसमें दो रायें नहीं हैं।

आज चीजें तो मिलती हैं इसमें शक नहीं है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो बोझी बाजार में हैं और उनकी माटेंज है। सीमेंट की है, कोल की है। मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को बोझा सा टाइमट कर देने की जरूरत है। मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ।

The supply of statements by the Minister is much more. It should be reduced and supply of commodities should be more.

मंत्रियों के स्टेटमेंट कुछ कम होने चाहिये और सप्लाई ज्यादा। बाव-झीकों की सप्लाई जरा कन्ट्रिब्यूली कम है। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि आप पहले कर दें और बाद में बोलें। आज होता यह है कि पहले आप स्टेटमेंट दे देते हैं लेकिन बाद में यह चीज पूरी नहीं होती है। इसका अर्थ बन नहीं होता है। मैं आपसे विनमता नहीं चाहता हूँ। मेरे पास बहुत से आपके स्टेटमेंट्स हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ।

Kindly reduce the supply of statements and increase the supply of commodities. That is the only remedy.

आपने अब तक जबरन बार्से ही कही हैं। आप देखें कि उनका इन्फ्लेक्शन कितना हुआ है। कितना होना चाहिये या नहीं हुआ है। बार्से पर और सप्लाई में अनाज बढ़ा है।

देश के मामले को ही ध्यान में। पिछले सरकार ने तेल के मामले में बहुत बंजालियन किया। करोड़ों रुपये के नुकसान बड़े और लोग उलझे डकार गए। उन से पैसा ले लिया और उलझे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। परिणाम यह है कि तेल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए। इस सरकार के जाने के बाद हमने तेल के परमिट्स लिए। यहाँ तेल मारा, रैप सीड माराया गया।

AN HON. MEMBER: This Government is repeating the mistakes of the earlier Government.

बी कंबर साल मुक्त : इस सरकार ने तेल की सप्लाई रेगुलर तरीके से की और उसको देश के कोने-कोने में ठीक दाम पर पहुँचाया, लेकिन एक मिकारत मेरो इस बारे में भी है और वह यह है कि इस सरकार के समय में जिन लोगों ने बंजालियन की वो उस पर कुछ पुरा पड़ गया है। वह पुरा क्यों पड़ गया है, यह तो मंत्री महोदय जानें इन में से कई केसेब की इन्फार्मिटी सी०की० धाई कर रही थी, उनका क्या हुआ? क्या उन में से कोई केस प्रवासात में गया था नहीं? अगर सरकार ब्लैक मार्किटियर्स के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है, तो उसको ऐसी परम्परा डालनी चाहिए कि वह बड़े बड़े लोगों को एम्प्लायरी पब्लिकमेंट दे। जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा, तब तक यह समस्या हल नहीं हो सकती।

हमारे देश की प्राबादी का लक्षण थाहा हिस्ता बिको-पावटी साइन है। सरकार को इस बाब की गारन्टी देनी चाहिये कि मजदूर, तेल, कपड़ा, बालें बाकि जो 8, 10 एंजिनियल कम्पोजिटीय हैं, वे बिको-पावटी साइन के लोगों को एक निश्चित दाम पर डकार मिलेगी और बाहे कुछ भी हो, बाहे किसना भी कम्पोजिटीय करने की बकरत बड़े बड़े किया जावेगा, लेकिन उन चीजों के दाम नहीं बढ़ाये जायेंगे।

बिल्की में हुय लोभे राशन में बड़े और बावक लेते हैं, अगर हमारा सक्शन बन्द की कर दिया जावे तो कोई कर्म नहीं पड़ता है लेकिन जो लोभ निकले बाबटी साइन है, उनके लिए गारन्टी होनी चाहिये कि बाहे काश्मीर हो या कन्याकुमारी, कोई इन्फार्म एरिया हो या बिल्की, देश में हर जगह उनको एंजिनियल कम्पोजिटीय एक पट्टिकर बाइस पर मुहैया की जायेंगी। दाम बाहे कितने भी बढ़ जायें, लेकिन उन लोगों को वे चीजें जहाँ राशियों पर मिलेगी, इस बात की गारन्टी होनी चाहिये।

हमारे देश में अभी तक जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसका ज्यादा फायदा ऊपर के लोगों को मिल रहा है। सरकार मांस में इलेक्ट्रिसिटी दे रही है, बड़े-बड़े जमींदार ही वहाँ उसका उपयोग करते हैं। सरकार को इलेक्ट्रिसिटी पर 200 करोड़ रुपये सालाना का लास होता है। इसी तरह से इरिगेशन पर भी सैकड़ों करोड़ रुपये का लास हो जाता है। इससे फायदा किसको हुआ है? छोटे लोगों, लैबलेस हरिजनों, छोटे किसानों को इसका फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि न वह इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं और न उनके पास इरिगेशन की फीसिलिटीय हैं, सिर्फ बड़े लैबलार्ड्स को ही इसका फायदा होता है। इसलिए सरकार को देखना चाहिये कि राशियों और सहरो में जो डेवलपमेंट होता है उसका ज्यादा लाभ नीचे के तबके के पास पहुँचे। जब तक ऐसा नहीं किया जायेगा, तब तक देश का कल्याण नहीं हो सकता है और हमारा समाजबाध भी जोखता रह जायेगा, उसका कोई मतलब नहीं होगा।

मैंने भी धारिया को एक किट्टी लिखी थी— इस बारे में पहले नी चर्चा हुई थी— कि रा-नीटीरियल का जितना दाम बढ़ता है क्या उसी हिस्सा के कंक्वमर को इन्सलने वाली चीजों का भी दाम बढ़ता है? मैंने

की संघर्ष करना शुरू :

25 बोलें बताई थी कि उन चीजों के रा-
नैटीरियल की कोमत तो गिर गई, लेकिन
नैन्यूरिबचरर के कंयूरर मुद्दे के डाम बढ़ा
दिये। मैंने कंयूरनी नान नान की लिखा था।
क्या सरकार के पास कोई कास्टिमर डिपार्टमेंट
है या नहीं? उसे अपने कास्टिमर डिपार्टमेंट
को संयुक्त करना चाहिये। अगर रा-
नैटीरियल का डाम न बढ़ने के बावजूब नैन्यूरि-
बचरर अपनी चीजों के डाम बढ़ा देता है तो
उसका गला पकड़ना चाहिये और उसको सजा
मिलनी चाहिए। मैं मांग करता हूँ कि हर एक
लेवल पर, नैन्यूरिबचरर, होल्सलर और
रिटेलर के लेवल पर सीमित नान प्राफिट
तब होना चाहिये।

यह तो नहीं होना चाहिये कि लूट हो रही
है जो यहाँ बिसकी जाए करे। मैं एक नहीं
पचासों उदाहरण दे सकता हूँ कि जहाँ पर रा-
नैटीरियल के डाम नहीं बढ़े लेकिन इन्वस्ट्री
वालों न बढ़ा दिये, होल्सलर ने बढ़ा दिए और
रिटेलर ने बढ़ा दिये। आप एक सीमित नान
प्राफिट हर एक लेवल पर करिए और
कास्टिमर भरिए ताकि जहाँ जितना रा-नैटीरियल
का डाम बढ़े उतना ही डाम बढ़ाने की उनको
आज्ञा दीजिए। उससे ज्यादा बढ़ाने की
आज्ञा नहीं मिलनी चाहिए।

एक जो और बिन्ता की बात है वह यह
है कि मनी सप्लाय हमारे देश में बहुत लेजी
से बढ़ रहा है। उसकी वजह से प्रभो डाम
नहीं बढ़े लेकिन उसका असर प्राये जाकर
पड़ेगा। इसके समय हर एक राज्य प्रोवर-
डाफ्ट कर रहा है। जैसे अभी हमारे निष्प ने
कहा कि केरल को और पैसा दो, केरल आ-बी
प्रोवर-डाफ्ट है और हर एक स्टेट का प्रोवर-
डाफ्ट है। उससे यह होगा कि अगुवाई बढ़ेगी
तो इकोनामिक मिनिस्ट्री के साथ एक
कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इकोनामिक
मिनिस्ट्री के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ मनी-
सप्लाय कम करनी चाहिए। मेरे मित्र के केरल

की बात नहीं और ब्रेस्ट बंचाल की बात नहीं।
मैं इच्छा करता हूँ, वहाँ तो अन्तः राष्ट्री की
सरकार नहीं है। ब्रेस्ट बंचाल ने क्या यह
सही नहीं है कि बिरला, टटा और बड़े बड़े
इन्वैस्टमिन्ट्स को वहाँ के लोक मिनिस्टर
ने बलाकर कहा कि प्राप यहाँ इन्वस्ट्री चाहिए।

Then don't accuse the Janata Party
for God's sake. You invite these big
industrialists and give them all faci-
lities, and yet you accuse us.

Even in Kerala it is the same. What
action have you taken? After all
public distribution is the work of the
State Government. What specific
steps have you taken in Kerala? Prac-
tically nothing and you only accuse
us and say, 'Give us money and we
will distribute.' That is a very easy
thing. Why don't you produce money?...

SHRI V. M. SUDHEERAN: We are
producing rubber, tea, cardamom and
so many other things and we earn a
substantial foreign exchange for the
country.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: You
have not levied any tax on big land-
lords. I accuse you....

SHRI V. M. SUDHEERAN: Guptaji
is ignorant of Kerala. Kerala is the
first State to implement land reforms.
I invite Mr. Gupta to come to Kerala
and study Kerala.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: I
will come.

मैं समझ कर रहा हूँ। मेरा कहना
यह है कि प्राप पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम
की योजना और ज्यादा करिए, प्राप कंयूरनान
की चीजें पब्लिक सेक्टर में जो बनाइये।
कब तक प्राप पब्लिक सेक्टर में प्रास-कंयूरनान
की एसेसिबल कीरीटिऑन नहीं बनाये
तब तक उसके डाम ठीक नहीं होगा। इससे
की की एसेसिबल कीरीटिऑन। मैं यह नहीं जानता
कि सारी चीजें सरकार से लेते हैं हमें सार्वकार

के पास पैसा नहीं है। केवल एक प्राइमरि वेड के रखा है किन्तु 2 करोड़ क्विंटल खरी लिए हैं। क्या वो कम्प्लेक्स प्रोग्राम खराने में ही ठीक है? बरतों की क प्रास्ता नहीं है। प्राय सारे प्राइमरि लेकर 65 करोड़ लोगों के प्राइमरि क्विंटल नहीं खर सकते हैं। इतकिए जी कीडन प्राक प्रुवमेंट है प्रुवनेस की में प्रतका स्वागत करता हूँ जो जनना पार्टी ने किया है। बम्बई में जब हम जाते थे तो हमारे रिस्तेदार कहते थे कि वो किलो प्रुवडा प्रावल लते आना। प्राव नहीं करते। प्रुव कहा प्रावल मिलता है। तो बेरा कहना यह है कि हमने कुछ प्रुवडे कम भी उठाए है, उसमें श्री इम्प्रुवमेंट की प्रुवकरत है श्री में मंत्री महीलय ने कहूंगा कि प्राय जो बिलो-प्रावटी लाइन के प्रांग हैं उनके लिए प्रावटी किलिए कि इतनी क्विंटल के ऊपर हम हर एक को देने। बाकी जयह दाम बढ़ नी जाये लेकिन उनके दाम नहीं बढ़ेंगे। इस विश्राम के प्राय में इसका मिडान्ट रूप से समर्थन करता हूँ।

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU (Chittoor): Shrimati Ahilya P. Rangnekar has brought a timely resolution which will help the government to know where it stands, if it wants to know. From the speeches of my friends it is clearly stated that the consumer prices are going up. The producers' prices are coming low and the traders and the middlemen are exploiting the nation. If it is so, then this should be corrected by the Government.

With regard to peasants I want to tell certain things. After the advent of Janata Party almost all the prices of agricultural commodities are going down. It is because this Government prohibited the exports of agricultural commodities, even the vegetables. That is why the prices are going down.

With regard to gur, what is happening? It was Rs. 130/- per quintal be-

fore Janata Party came to power. Now it is Rs. 60/- per quintal. Therefore, it is slightly more than 1/3rd.

What about Coriander? It was Rs. 300/- per bag. Now it is Rs. 80 per bag. What about tobacco? It was selling at Rs. 10/- per kg. Now it is Rs. 3/- to Rs. 4/-. What about paddy? What about wheat? Support prices are declared. Whether they are remunerative or not the agricultural Price Commission declared support prices. But whether the surpluses are purchased or not is the question? Where are the surpluses of wheat and paddy in our country? Shri Mohan Dharis himself has stated that there are surpluses in Andhra Pradesh and there are deficits in other States. That means that the procurement and distribution system is not perfect in this country according to the Minister's statement. Therefore, is it not necessary to correct that? Now when the prices of agricultural commodities are going down can the Government keep quiet? My friend here has said that in Kerala where there is deficit in food grains the agricultural producers are suffering very much especially the paddy growers. What happened in Andhra Pradesh? When cyclone came the paddy growers suffered very much, but the Central Government refused to purchase paddy. Even there, as in Kerala, the State Government has to bear the brunt of purchasing paddy. Why is this Government shedding responsibility of protecting the agriculturists in States? It is its responsibility to purchase these things and to stabilise the prices. Therefore, there must be a solution. What is the solution?

There is the Agricultural Price Commission in our country. It has been constituted in 1965. Till now it is not reconstituted and, therefore, I request the hon. Minister to see that it is reconstituted immediately. Agricultural price Commission is not having proper representation of the

[Shri P. Rajagopal Naidu]

agriculturists. There is only one representative—i.e., from wheat zone. There is no representative at all for paddy—which is the largest growing area in our country. Therefore, when it is reconstituted, it must have proper representation of the producers so that remunerative prices are fixed. They say, support prices are being paid. Well, what is the support price which the Agricultural Prices Commission is fixing? This is my question. What is the basis? There must be a basis for these things. The basis for the fixation of the support price must be that the price must be remunerative to the farmers. It is not remunerative at all. The APC should be asked not to fix up any unremunerative price. This is my submission. They should fix up only remunerative price.

Then, my next point is this. All the surpluses must be bought by the Government. There must be suitable machinery provided for this purpose. There must be enough number of godowns also. There must be a comprehensive plan for this purpose. Where is the plan for it? There is nothing in this regard in the fifth plan or the sixth plan. The Janata Government is boasting that it is for the rural people, it is for the kisans and so on and the agricultural people. But what is happening here? What is being done is nothing but depriving the agricultural classes of their dues. If the Government in reality and sincerely interested in coming to the rescue of the agriculturists, then, I submit, Sir, that they must reconstitute the Agricultural Prices Commission and they must buy all their surplus. This is my respectful submission.

Sir, we are becoming surplus in wheat. We are becoming surplus in rice. Are we exploring the markets outside? There must be necessary export promotion work undertaken in this behalf. We should develop our Export Promotion Council in this regard.

SHRI DINEN BHATTACHARYA: Sir, I would like to move a Motion for suspending the Rules, so that I may move my Resolution which is No. 3 in the List.... (Interruption).

MR. CHAIRMAN: Order please. You are a senior Parliamentarian, Mr. Dinen Bhattacharya. You know the Rules of Business very well. This discussion will continue upto 5-30. Then we have Half-an-hour discussion after that. Your Resolution is there and that will be taken up on the next day allotted for the Private Members' Resolutions.

SHRI DINEN BHATTACHARYA: I will just move my Resolution. I will not speak.

MR. CHAIRMAN: Mr. Dinen Bhattacharya, you understand all these things. You are a senior Member; you are a senior Parliamentarian.

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: With regard to the distribution of essential commodities, what is the Government doing? The Government is always very particular about the organised classes and about the town people, and about the white-collared people. It is not at all caring for the small farmers, the agriculturists or the small artisans. It is not caring for these poor people in the villages.

SHRI DINEN BHATTACHARYA: Sir, in the case of Mr. Samar Guha's Resolution, the same thing was done. Certain other Resolution was under discussion. That was postponed for the time-being, for two minutes or so. Mr. Samar Guha moved that Resolution standing in his name.

MR. CHAIRMAN: If it was moved it was discussed on the next day.

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: In the countryside, they are not getting cloth they are not getting herosene, they are not getting diesel oil, they are not getting their agricultural implements.

MR. CHAIRMAN: Mr. Rajagopal Naidu, you will continue on the next day, allotted for Private Members' Business.

We pass on to the next item.

SHRI DINEN BHATTACHARYA: Will you permit me to move my Resolution, Sir?

MR. CHAIRMAN: You know the rules. You know everything. You are teaching many Parliamentarians. Please don't break the rule.

SHRI DINEN BHATTACHARYA: You can suspend the Rule....

MR. CHAIRMAN: Please resume your seat, Mr. Dinan Bhattacharya. I appeal to you.

Now, we will go to the next item.

RE: CORRESPONDENCE BETWEEN THE PRIME MINISTER AND THE FORMER HOME MINISTER

PROF. P. G. MAVALANKAR (Gandhinagar): Before you go to the next item, I would like to make my submission on a Point of Order.

We have just come to understand that something has been decided about the correspondence between the Prime Minister and the former Home Minister.

I hope you know that there was a lot of discussion in this House. Now information has reached us—it is for you to contradict it if it is wrong. But, it has reached us that several honourable colleagues of ours, who are representing various groups are being invited to the Speaker's Committee Room to inspect the correspondence.

Now, I want to know whether it is a fact. If so, want to raise an

objection on two grounds—firstly, have you ever decided this matter in the House; all that I know of is the fact that this was being discussed when the matter was kept pending until the Speaker decided and informed the House. Now, we have not disposed of this matter; nor have we got any finality from the hon. Speaker. I am told in the other House, the hon. Chairman of the House, decided the course of action and they are doing it. Now it is not for us to comment upon what happened in the other House. It will not be right and proper to do that also. But my point is that if something happened in that House and the same thing is being repeated here without the knowledge of the House by the hon. Speaker about the whole position, is it in order? This is my point number one. Secondly, how is it that only some are invited? I do not know why I have not been asked for it. In the other House, some Independents have been invited. In the other House some Independents have also been asked to see it. I have not got any information. All I am saying is, this is a point on which I stand on principle.

No announcement was made. I have no information; I have no intimation. Apart from that, my main point is that the House has not been kept informed about this at all; the House has not been taken into confidence; nor has the Speaker given us any decision. And if something happens without all this in the Speaker's Committee Room, I may sorry; I must raise my voice of protest.

I want your guidance from you.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA (Begusarai): Mr. Chairman, may I make a submission? The matter was raised in the House and almost all the Group Leaders were associated with the demand for the papers; the exchange of letters to be placed either on the table of the House or in the manner in which it was thought fit. Now, whatever the decision taken, I